# HRA AN USIUSION Che Gazette of India

असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II —खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY** 

सं. 109] No. 109] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2003/माघ 15, 1924

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2003/MAGHA 15, 1924

# भारतीय रिजर्व बैंक

अधिसुचना

मुंबई, 22 जनवरी, 2003

का.आ. 131(अ).— प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 29ए के अंतर्गत भारत सरकार की दिनांक 1 मार्च 2000 की अधिसूचना सं.183(अ) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक -

- (i) यह मानते हुए कि संपूर्ण भारत में प्रतिभूतियों के अवांछनीय सट्टे को रोकना आवश्यक है, एतद्द्वारा यह घोषणा करता है कि उक्त अधिनियम के क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति.
- (क) उक्त अधिनियम, संबंधित शेयर बाजार के नियमों, विनियमों तथा उपविधियों के अंतर्गत अनुमत हाजिर सुपुर्दगी संविदा अथवा मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में की जानेवाली संविदाओं को छोड़कर सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण से संबंधित प्रतिभूतियों तथा मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों की बिक्री अथवा खरीद के लिए संविदा नहीं करेगा।
- (ख) बांडों, डिबेंचरों, डिबेंचर शेयरों, प्रतिभूतिकृत ऋण तथा किसी व्यक्ति अथवा केंद्र अथवा राज्य के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी निकाय द्वारा जारी की गयी अन्य ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाएं नहीं करेगा।

"बशर्ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों पर निम्नलिखित व्यक्तियों/इकाइयों द्वारा सभी सरकारी प्रतिभूतियों में हाजिर वायदा संविदाएं की जाएं।

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में सहायक सामान्य बही (एस.जी.एल) खाता रखनेवाला कोई व्यक्ति या कोई संस्था अथवा

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत कोई अनुसूचित बैंक अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनियों से इतर) अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत कोई आवासीय वित्त कंपनी, अथवा सेबी में पंजीकृत कोई म्युच्युअल फंड कंपनी, अथवा बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण में पंजीकृत कोई बीमा कंपनी जिसका किसी ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था के पास गिल्ट खाता हो, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक के किसी लोक ऋण कार्यालय में सीएसजीएल खाता बनाये रखने के लिए अनुमित दी हो, अथवा

(ग) कोई अन्य व्यक्ति, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के किसी लोक ऋण कार्यालय में सीएसजीएल खाता बनाये रखने की अनुमति दी गयी हो, ऐसे व्यक्ति अथवा इकाई के साथ जिसका गिल्ट खाता हो,

बशर्ते कि कोई भी हाजिर वायदा करार दो ऐसे व्यक्तियों या इकाइयों के बीच न किया जाए जिनके ऐसे एक ही व्यक्ति अथवा ऐसी इकाई के पास गिल्ट खाते हों जिनका भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में सीएसजीएल खाता हो।

बशर्ते यह भी कि कोई ऐसा हाजिर वायदा करार भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में एसजीएल खाता रखनेवाले किसी व्यक्ति अथवा इकाई का अपने पास ही गिल्ट खाता रखनेवाले दूसरे व्यक्ति अथवा इकाई के साथ न किया जाए।

बशर्ते यह भी कि सभी हाजिर वायदा करार भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में रखे एसजीएल खाते अथवा सीएसजीएल खाते के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली शर्तों के अनुसरण में संपादित किये जायेंगे।

बशर्ते यह भी कि संविदा की शर्तों के अनुसार संविदा की समाप्ति तक बकाया तैयार वायदा संविदाएं बनी रहेंगी।

बशर्ते यह भी कि प्रमाणित स्टॉक एक्सचेंजों पर की गई ऐसी संविदाऐं निम्नानुसार की जाऐंगी:-

- (क) प्रतिभूतियां संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) अथवा प्रतिभूतियां और भारतीय विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों अथवा उपविधियों अथवा उक्त अधिनियमों के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति अथवा विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएंगी।
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अंतर्गत अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) अथवा विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम 1999 के अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएंगी।

(ग) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाओं में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार की जाएंगी।

# स्पष्टीकरण

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए:

- (क) अनुसूचित बैंक से तात्पर्य भारतीय रिजार्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किसी बैंक से है।
- (ख) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 के खण्ड (एफ) में यथा परिभाषित कंपनी से है।
- (ग) म्युच्युअल फंड से तात्पर्य ऐसा फंड जो सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (म्युच्युअल फंड) विनियमावली, 1996 के नियम 2 के खंड (क्यु) में यथा परिभाषित है।
- (घ) कांस्टीट्यूएंट सबसिडीयरी जनरल लेजर (सीएसजीएल) एकाउंट से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत किसी बैंक अथवा किसी व्यक्ति द्वारा उसके ग्राहकों की ओर से सरकारी प्रतिभूतियां धारण करने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालयों में खोले गये और रखे गये सबसिडीयरी जनरल लेजर एकाउंट से है।
- (ङ) गिल्ट एकाउंट से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में सीएसजीएल खाता खोलने और रखने के लिए अनुमत किसी बैंक अथवा किसी व्यक्ति के पास किसी व्यक्ति द्वारा खोला और रखा गया प्रतिभूति खाता।

यह अधिसूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहली मार्च 2000 को जारी अधिसूचना सं.एसं.ओ.185(ई) का अधिक्रमण करते हुए जारी की जा रही है।

> [सं. आइडीएमसी. 2/10.02.01/2002-2003] मुहम्मद ताहिर, कार्यपालक निदेशक

## RESERVE BANK OF INDIA

## **NOTIFICATION**

Mumbai, the 22nd January, 2003

- S.O. 131(E).— In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India under section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) vide Government of India Notification No. 183(E) dated 1<sup>st</sup> March, 2000, issued under Section 29A of the Act ibid, the Reserve Bank of India
  - being of the opinion that it is necessary to prevent undesirable speculation in securities in the whole of India, hereby declares that no person in the territory to which the Act extends, shall, enter into any
  - (a) contract for the sale or purchase of Government securities, gold related securities and money market securities other than spot delivery contract or such other contract traded on a recognised stock exchange, as is permissible under the said Act, rules and bye-laws of such stock exchange.
  - (b) ready forward contracts in bonds, debentures, debenture stock, securitised debt, and other debt securities issued by any person or any body corporate established by or under a Central or State Act.
  - Provided that ready forward contracts may be entered into in all Government securities, in accordance with the terms and conditions as may be specified by the Reserve Bank of India, by the following persons/entities
  - a) any person or entity holding a Subsidiary General Ledger account with the Public Debt Office of the Reserve Bank of India
  - b) a scheduled bank or a non-banking financial company registered with Reserve Bank of India (other than Government Companies as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956) or a housing finance company registered with National Housing Bank, or a mutual fund registered with Securities and Exchange Board of India, or an insurance company registered with Insurance Regulatory and Development Authority, holding a Gilt account with any person or entity permitted by Reserve Bank of India to maintain Constituent Subsidiary General Ledger account with Public Debt Office of the Reserve Bank of India or
  - c) any other person specifically permitted by Reserve Bank of India, holding a Gilt account with any person or entity permitted by Reserve Bank of India to maintain Constituent Subsidiary General Ledger account with Public Debt Office of the Reserve Bank of India;

Provided further that no ready forward contracts may be entered into between two persons or entities both maintaining Gilt accounts with same person or entity maintaining Constituent Subsidiary General Ledger account with the Public Debt Office of the Reserve Bank of India.

Provided further that no ready forward contracts may be entered into between a person or entity maintaining Subsidiary General Ledger account with Public Debt Office of the Reserve Bank of India with another person or entity maintaining a Gilt account with itself.

Provided further that all ready forward contracts shall be settled through a Subsidiary General Ledger account or a Constituent Subsidiary General Ledger account maintained with the Public Debt Office of Reserve Bank of India, in accordance with the terms and conditions as may be specified by the Reserve Bank of India

Provided further that the outstanding ready forward contracts shall continue till termination of the contracts as per the contractual terms:

Provided further that such contracts entered into on the recognised stock exchanges shall be entered in accordance with-

- a) the rules or regulations or the bye-laws made under the Securities Contracts (Regulation) Act 1956,(42 of 1956) or the Securities and Exchange Board of India Act 1992(15 of 1992) or the directions issued by the Securities and Exchange Board of India under the said Acts;
- b) the rules made or guidelines or directions issued under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or the Foreign Exchange Management Act, 1999 by the Reserve Bank of India.
- c) the provisions contained in the notifications issued by the Reserve Bank of India under the Securities Contracts (Regulation) Act 1956 (42 of 1956)

# Explanation

For the purpose of this notification:

- a) "scheduled bank" means a bank included in the second schedule of Reserve Bank of India Act, 1934.
- b) "non-banking financial company" means a company as defined in clause (f) of Section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934.
- c) "mutual fund" means a fund as defined in clause (q) of the Regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996.
- d) "Constituent Subsidiary General Ledger account" means a Subsidiary General Ledger account opened and maintained with the Public Debt Office of the Reserve Bank of India, by a bank or any other person permitted by the Reserve Bank of India, for the purpose of holding Government securities on behalf of its constituents.

e) "Gilt account" means a securities account opened and maintained by any person with a bank of or any other person permitted by the Reserve Bank of India to open and maintain Constituent Subsidiary General Ledger account with the Public Debt Office of the Reserve Bank of India.

This notification is issued by Reserve Bank of India, in supersession of the notification no. S.O.185 (E) dated 1st March 2000 issued by it.

[No. IDMC. 2/10.02.01/2002-2003] MOHAMMAD TAHIR, Executive Director